International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 15 Issue 06, June 2025,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

भू- राजनीति में चीन का बढ़ता प्रभाव : अवसर और चुनौतियाँ

Ajay Kumar, Research Scholar,
Supervisor Name – Dr. Vijender Kumar
Department of Political Science, SJJTU, Jhunjhunu (Rajasthan). Emailid:
Ajaykundu2511@gmail.com
DOI:ijmra.ijrss.33878.22990

संक्षेप

भू-राजनीति में चीन का बढ़ता प्रभाव वैश्विक स्तर पर कई अवसर और चुनौतियाँ लेकर आया है। चीन की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक परियोजनाओं जैसे 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' ने विकासशील देशों के लिए निवेश और व्यापार के नए अवसर उत्पन्न किए हैं, जिससे वैश्विक आर्थिक एकीकरण में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, चीन की तकनीकी प्रगति और सैन्य शक्ति में तेजी से वृद्धि ने उसे क्षेत्रीय और वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है। लेकिन, इस प्रभाव के साथ कई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। क्षेत्रीय विवाद, विशेषकर दक्षिण चीन सागर में, और सीमा संघर्ष जैसे मुद्दे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ा रहे हैं। कई देशों के लिए चीन की आर्थिक निर्भरता उनकी स्वतंत्र नीतियों और सुरक्षा पर दबाव डाल रही है। इसके साथ ही, चीन की बढ़ती राजनीतिक और आर्थिक दखलअंदाजी से विकासशील देशों की संप्रभुता प्रभावित हो सकती है। वैश्विक शक्ति संतुलन बिगड़ने का खतरा भी उत्पन्न हो गया है, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए, चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए रणनीतिक साझेदारी, कूटनीति और वैश्विक सहयोग आवश्यक है ताकि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनी रहे।

मुख्य शब्द: चीन का प्रभाव, बेल्ट एंड रोड, आर्थिक अवसर, क्षेत्रीय तनाव, वैश्विक शक्ति संतुलन।

प्रस्तावना

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भू-राजनीति (Geopolitics) की भूमिका दिन-प्रतिदिन अधिक जटिल और प्रभावशाली होती जा रही है, और इस परिदृश्य में चीन का बढ़ता प्रभाव एक निर्णायक कारक के रूप में उभर रहा है। 21वीं सदी को 'एशियाई सदी' कहे जाने का प्रमुख आधार चीन की तीव्र आर्थिक, सैन्य और तकनीकी प्रगति है, जिसने उसे एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद चीन ने अपनी विदेश नीति और सामरिक दृष्टिकोण में रणनीतिक बदलाव किए हैं, जिनमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI), दक्षिण चीन सागर में सैन्य विस्तार, और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका तथा एशिया में निवेश जैसे कदम शामिल हैं। भारत सहित अनेक विकासशील देशों के लिए

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 15 Issue 06, June 2025,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

यह प्रभाव एक ओर अवसंरचना विकास और आर्थिक सहयोग के अवसर प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर संप्रभुता, रणनीतिक निर्भरता और सुरक्षा के नए संकट भी उत्पन्न करता है। भारत-चीन संबंधों में सीमा विवाद, व्यापारिक असंतुलन और राजनीतिक मतभेद लंबे समय से विद्यमान हैं, जिन्हें चीन की नई आक्रामक कूटनीति और सैन्य विस्तारवाद ने और अधिक जटिल बना दिया है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों द्वारा बनाए गए रणनीतिक गठबंधन (जैसे QUAD) इस बढ़ते प्रभाव का सामूहिक प्रतिकार करने का प्रयास कर रहे हैं। चीन न केवल अपनी 'हार्ड पावर' के माध्यम से दबदबा बना रहा है, बल्कि सांस्कृतिक कूटनीति, वैश्विक मीडिया और तकनीकी नेटवर्क के ज़रिये 'सॉफ्ट पावर' के माध्यम से भी अपना प्रभाव फैला रहा है। ऐसे में भारत और अन्य राष्ट्रों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे संतुलित रणनीति अपनाते हुए चीन के साथ प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों के लिए तैयार रहें। इस शोध का उद्देश्य चीन के बढ़ते भू-राजनीतिक प्रभाव का विश्लेषण करना है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विश्व राजनीति में यह परिवर्तन किस प्रकार अवसर और चुनौतियों दोनों का निर्माण करता है तथा भारत जैसे राष्ट्रों के लिए भविष्य की कूटनीतिक दिशा क्या होनी चाहिए।

अध्ययन का उद्देश्य

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य चीन के भू-राजनीतिक प्रभाव में हो रहे विस्तार का समग्र विश्लेषण करना है, जिससे इसके द्वारा उत्पन्न अवसरों और चुनौतियों को स्पष्ट रूप से समझा जा सके। चीन के आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक उत्थान ने वैश्विक और क्षेत्रीय शक्ति संरचना को बदल दिया है, जिसका असर भारत और उसके पड़ोसी देशों पर विशेष रूप से देखा जा रहा है। इस शोध में चीन की विदेश नीति, निवेश रणनीतियाँ, सीमा विवाद, तथा बहुपक्षीय मंचों में उसकी भूमिका का गहन विवेचन किया जाएगा। साथ ही, यह अध्ययन भारत सहित क्षेत्रीय देशों के लिए इस बढ़ते प्रभाव के प्रभावी प्रबंधन और रणनीतिक विकल्पों की पहचान करने का प्रयास करेगा। इसका उद्देश्य नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और जन समुदाय के लिए एक समृद्ध संदर्भ प्रदान करना है, जिससे वे वर्तमान भू-राजनीतिक चुनौतियों और अवसरों का बेहतर सामना कर सकें।

भू-राजनीति की परिभाषा और महत्व

भू-राजनीति (Geopolitics) वह अध्ययन क्षेत्र है जो भूगोल, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, शक्ति-संतुलन और वैश्विक रणनीतियों के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण करता है। इसमें यह समझने का प्रयास किया जाता है कि कैसे किसी देश की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, सीमाएं, समुद्री मार्ग, जलवायु

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 15 Issue 06, June 2025,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

और स्थलाकृति उसकी विदेश नीति, सुरक्षा रणनीति तथा वैश्विक शक्ति-संतुलन को प्रभावित करते हैं। भू-राजनीति का उद्गम 19वीं सदी में हुआ, जब महान साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने विस्तार की नीति में अपने भौगोलिक लाभों का प्रयोग किया। हाफोर्ड मैकिंडर, अल्फ्रेड महन और निकोलस स्पाइकमैन जैसे विद्वानों ने विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से यह बताया कि किसी क्षेत्र विशेष पर नियंत्रण प्राप्त करने से वैश्विक प्रभुत्व स्थापित किया जा सकता है। आज के वैश्विक युग में जब तकनीक, अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और सैन्य शक्ति एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हैं, तब भू-राजनीति केवल सीमाओं या युद्धों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह वैश्विक शासन, बहुपक्षीय संगठनों, ऊर्जा सुरक्षा, साइबर स्पेस और अंतरिक्ष नीति तक विस्तारित हो चुकी है। वर्तमान में अमेरिका, चीन, रूस, भारत, जापान और यूरोपीय संघ जैसे राष्ट्र अपनी भू-राजनीतिक स्थिति को आधार बनाकर वैश्विक नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विशेषकर भारत जैसे देशों के लिए, जिनकी सीमाएँ विविध राष्ट्रों से मिलती हैं और जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जल मार्गों और पर्वतीय सीमाओं से घिरे हैं, भू-राजनीति को समझना और रणनीतिक नीतियाँ बनाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यह विषय नीति-निर्माताओं को न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में दिशा देता है, बल्कि आर्थिक साझेदारी, ऊर्जा कूटनीति, सीमा विवाद समाधान, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में संतुलन साधने के लिए भी उपयोगी होता है। इसलिए भू-राजनीति न केवल एक अकादमिक विषय है, बल्कि यह राष्ट्रों की दीर्घकालिक स्थिरता, संप्रभुता और विकास पथ को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण भी है।

वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भू-राजनीति की भूमिका

वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भू-राजनीति की भूमिका पहले से कहीं अधिक व्यापक, जटिल और निर्णायक बन चुकी है। 21वीं सदी में जहां एक ओर वैश्वीकरण, तकनीकी विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए आयाम खुल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा, सामरिक तनाव, संसाधनों पर नियंत्रण और क्षेत्रीय प्रभुत्व की होड़ ने भू-राजनीतिक समीकरणों को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। रूस-यूक्रेन युद्ध, चीन की आक्रामक विस्तारवादी नीति, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सैन्य गठबंधन, और मध्य एशिया में ऊर्जा स्रोतों पर वर्चस्व की लड़ाई—ये सभी घटनाएँ इस बात का प्रमाण हैं कि वैश्विक स्तर पर भू-राजनीति न केवल सैन्य रणनीतियों को दिशा देती है, बल्कि आर्थिक नीतियों, कूटनीति, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और अंतरिक्ष क्षेत्र तक को प्रभावित करती है। आज के दौर में 'स्मार्ट पावर' की अवधारणा, जिसमें सैन्य शक्ति के साथ-साथ तकनीकी व आर्थिक प्रभुत्व भी शामिल है, भू-राजनीति की नई परिभाषा बन चुकी है। उदाहरण के

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 15 Issue 06, June 2025,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

लिए, चीन द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से व्यापार मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करना या अमेरिका का QUAD व AUKUS जैसे गठबंधनों में नेतृत्व करना, वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, महामारी और जल संकट जैसे पारंपरिक रूप से गैर-सामरिक माने जाने वाले विषय भी अब भू-राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि ये वैश्विक स्थिरता और संसाधनों की उपलब्धता को सीधे प्रभावित करते हैं। भारत जैसे उभरते राष्ट्रों के लिए यह समय अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जब उन्हें न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी है, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों पर सक्रिय भागीदारी भी निभानी है। इस संदर्भ में भू-राजनीति केवल नीति निर्धारण का उपकरण नहीं, बल्कि वैश्विक नेतृत्व की योग्यता का पैमाना बन चुकी है, जो यह तय करता है कि कौन सा राष्ट्र किस हद तक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।

चीन की वैश्विक भूमिका का उदय

- **आर्थिक, सैन्य और तकनीकी विकास की संक्षिप्त झलक**

चीन का वैश्विक उदय बीते कुछ दशकों में अभूतपूर्व गति से हुआ है, जिसने उसे एक उभरती शक्ति से विश्व राजनीति का केंद्रबिंदु बना दिया है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो चीन ने 1978 में शुरू की गई "ओपन डोर पॉलिसी" के माध्यम से अपने बाजारों को वैश्विक निवेश के लिए खोल दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। चीन की GDP, विनिर्माण उत्पादन, निर्यात और विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े उसकी आर्थिक ताकत के प्रमाण हैं। चीन ने न केवल श्रम-प्रधान उद्योगों में, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), 5G, क्वांटम कंप्यूटिंग, और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। सैन्य दृष्टि से, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) का आधुनिकीकरण, अत्याधुनिक हथियार प्रणालियाँ, समुद्री नौसैनिक शक्ति में वृद्धि और दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप निर्माण इसके क्षेत्रीय और वैश्विक सैन्य प्रभुत्व की रणनीति को दर्शाते हैं। चीन का रक्षा बजट अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है, जो उसकी सामरिक महत्वाकांक्षा को स्पष्ट करता है। तकनीकी क्षेत्र में भी चीन ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अमेरिका और यूरोप को चुनौती दी है; HUAWEI, TikTok, ZTE जैसी कंपनियाँ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रभावी भूमिका निभा रही हैं।

"द ड्रैगन राइज़िंग" – चीन की विदेश नीति की रूपरेखा

चीन की विदेश नीति अब पारंपरिक 'गुटनिरपेक्षता' से आगे बढ़कर 'सक्रिय वैश्विक उपस्थिति' की ओर अग्रसर हो चुकी है, जिसे विश्लेषक अक्सर "द ड्रैगन राइज़िंग" (The Dragon Rising) की संज्ञा देते

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 15 Issue 06, June 2025,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ने "चाइनीज ड्रीम", "साउथ-साउथ कोऑपरेशन", और "साझा भविष्य वाला वैश्विक समुदाय" जैसे नारे देकर अपनी कूटनीति को एक नया आयाम दिया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) इसका प्रमुख उदाहरण है, जो लगभग 150 देशों में बुनियादी ढांचे, व्यापार और निवेश के माध्यम से चीन का रणनीतिक विस्तार सुनिश्चित करता है। इसके साथ-साथ चीन संयुक्त राष्ट्र, WTO, BRICS, SCO और G20 जैसे बहुपक्षीय मंचों पर अपनी भागीदारी को और प्रभावशाली बना रहा है, जिससे वह वैश्विक व्यवस्था को अपनी अनुकूलता के अनुसार ढालना चाहता है। चीन की "वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी" – जो आक्रामक और प्रत्यक्ष है – भी इस बात की द्योतक है कि वह अब अपनी बात को सशक्त रूप से रखने और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा में पीछे नहीं हटेगा। चीन की यह रणनीति उसे न केवल एक आर्थिक शक्ति, बल्कि एक राजनीतिक और वैचारिक ताकत के रूप में स्थापित कर रही है, जो मौजूदा वैश्विक शक्ति संतुलन को चुनौती देती है।

भू-राजनीतिक परिदृश्य में चीन का प्रभाव क्षेत्र

- **एशिया-प्रशांत क्षेत्र**

चीन का प्रभाव सबसे पहले और सर्वाधिक गहराई से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में महसूस किया गया है, जहाँ वह न केवल एक आर्थिक दिग्गज के रूप में उभरा है, बल्कि एक सैन्य और कूटनीतिक ताकत के रूप में भी स्थापित हुआ है। दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा कृत्रिम द्वीपों का निर्माण, सैन्य चौकियों की स्थापना और विवादित जल क्षेत्रों पर अपना दावा—यह सब चीन के क्षेत्रीय प्रभुत्व की महत्वाकांक्षा को उजागर करता है। यह क्षेत्र जापान, वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान और मलेशिया जैसे देशों के लिए सुरक्षा चिंता का विषय बन चुका है। इसके जवाब में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र QUAD (Quadrilateral Security Dialogue) के माध्यम से एक सामूहिक रणनीतिक ढाँचा तैयार कर रहे हैं। इस क्षेत्र में चीन की आर्थिक भूमिका भी अत्यधिक प्रभावशाली है, क्योंकि वह क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (जैसे RCEP) और डिजिटल सिल्क रोड जैसी पहलों के माध्यम से आर्थिक वर्चस्व स्थापित कर रहा है।

- **हिंद महासागर क्षेत्र**

हिंद महासागर चीन के लिए एक रणनीतिक जीवनरेखा के समान है, क्योंकि इसके माध्यम से वह मध्य-पूर्व और अफ्रीका से ऊर्जा आपूर्ति करता है। इस क्षेत्र में चीन की पहुँच बढ़ाने के लिए वह 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति के तहत श्रीलंका (हम्बनटोटा), म्यांमार (कयाउकप्यू), पाकिस्तान (ग्वादर) और

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 15 Issue 06, June 2025,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

जिबूती जैसे स्थानों पर बंदरगाह और सैन्य-सुविधाओं का निर्माण कर चुका है। इससे भारत की सामरिक चिंता बढ़ी है, क्योंकि चीन की नौसैनिक मौजूदगी अब उसकी समुद्री सीमाओं के बहुत निकट पहुँच चुकी है। भारतीय नौसेना और रणनीतिक नीति निर्माताओं के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण भू-राजनीतिक परिदृश्य निर्मित कर रहा है, जिसमें संतुलन बनाए रखना अनिवार्य हो गया है।

- **अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में निवेश और रणनीतिक साझेदारी**

चीन ने अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपने निवेश और कूटनीतिक प्रयासों के ज़रिए भी अपने वैश्विक प्रभाव को बहुत अधिक विस्तार दिया है। अफ्रीका में चीन ने सड़कों, रेलमार्गों, ऊर्जा संयंत्रों और खनिज संसाधनों के दोहन से संबंधित परियोजनाओं में भारी निवेश किया है। इसके बदले चीन को प्राकृतिक संसाधन, राजनीतिक समर्थन और रणनीतिक पहुँच प्राप्त होती है। इसी तरह, लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील, वेनेज़ुएला, इक्वाडोर और अर्जेंटीना जैसे देशों में चीन का व्यापार, तकनीकी सहयोग और अवसंरचना निवेश लगातार बढ़ रहा है। ये प्रयास न केवल आर्थिक हैं, बल्कि अमेरिका के पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र में चीन की रणनीतिक घुसपैठ के संकेत भी देते हैं, जिससे वाशिंगटन के लिए यह चिंता का विषय बन चुका है।

- **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) की भूमिका**

चीन के वैश्विक प्रभाव का सबसे व्यापक और स्पष्ट उदाहरण बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) है, जिसे राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी रणनीति माना जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य एशिया, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना है—जिसमें सड़कों, रेलमार्गों, बंदरगाहों, डिजिटल संचार और ऊर्जा पाइपलाइनों का निर्माण शामिल है। यह पहल न केवल आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे चीन को इन क्षेत्रों में रणनीतिक पहुँच, कूटनीतिक समर्थन और दीर्घकालिक प्रभाव प्राप्त होता है। हालांकि, यह परियोजना कई देशों में "ऋण-जाल कूटनीति" (Debt Trap Diplomacy) का आरोप भी झेल रही है, जहाँ अत्यधिक कर्ज के चलते देश अपनी सम्पत्ति या संप्रभुता गिरवी रखने को मजबूर हुए हैं। इसके बावजूद BRI चीन की उस भू-राजनीतिक रणनीति का केंद्र है जिसके ज़रिए वह न केवल वैश्विक व्यापार मार्गों पर नियंत्रण चाहता है, बल्कि एक वैकल्पिक वैश्विक नेतृत्व भी प्रस्तुत करना चाहता है।

भारत और अन्य पड़ोसी देशों पर चीन के प्रभाव

- **भारत-चीन संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 15 Issue 06, June 2025,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

भारत और चीन, दो प्राचीन सभ्यताएं, ऐतिहासिक रूप से बौद्ध धर्म, व्यापारिक मार्गों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान से जुड़ी रही हैं। हालांकि आधुनिक काल में 1950 के दशक में जब भारत ने "हिंदी-चीनी भाई-भाई" का नारा दिया, तब दोनों देशों के संबंध मैत्रीपूर्ण प्रतीत हुए, लेकिन यह सहयोग ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। 1962 के भारत-चीन युद्ध ने दोनों देशों के संबंधों में गहरा अविश्वास भर दिया, जिसका प्रभाव आज तक बना हुआ है। उसके बाद से दोनों देशों ने समय-समय पर संबंध सुधारने का प्रयास किया, विशेष रूप से 1988 के बाद राजीव गांधी की चीन यात्रा के साथ एक नई शुरुआत हुई, लेकिन द्विपक्षीय मतभेद अब भी अनेक मुद्दों पर कायम हैं। चीन का पाकिस्तान से रणनीतिक सहयोग, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार में उसकी बढ़ती उपस्थिति, और भारत के चारों ओर 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति से भारत की सामरिक चिंताएं लगातार बढ़ी हैं। बीआरआई में भारत की अनुपस्थिति और क्वाड जैसे गठबंधनों में उसकी सक्रियता इस प्रतिस्पर्धा को और स्पष्ट बनाती है।

- **सीमा विवाद (LAC, डोकलाम, अरुणाचल)**

भारत-चीन संबंधों का सबसे विवादास्पद पहलू उनका सीमा विवाद है, जो तीन प्रमुख क्षेत्रों में केंद्रित है: लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC), सिक्किम-भूटान-तिब्बत त्रिकोण में डोकलाम, और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख में 2020 की गलवान घाटी झड़प ने भारत-चीन संबंधों को फिर से तनावपूर्ण मोड़ पर ला खड़ा किया, जहाँ दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ और सैनिकों की जान गई। डोकलाम संकट (2017) में भारत ने भूटान की सुरक्षा के हित में हस्तक्षेप करते हुए चीन के सड़क निर्माण को रोका, जिससे एक बार फिर दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध उत्पन्न हुआ। अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी चीन बार-बार आपत्ति जताता रहा है और उसे "दक्षिण तिब्बत" कहकर भारत की संप्रभुता को चुनौती देता रहा है। इन सीमा विवादों के कारण दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी बनी हुई है और सीमा वार्ताएं भी अब तक निर्णायक समाधान नहीं दे सकी हैं।

- **व्यापारिक असंतुलन और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा**

भारत और चीन के बीच आर्थिक संबंधों में व्यापारिक असंतुलन एक प्रमुख चिंता का विषय है। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है, लेकिन यह साझेदारी असंतुलित है क्योंकि भारत चीन से अधिक आयात करता है और अपेक्षाकृत कम निर्यात करता है। मोबाइल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्युटिकल कच्चा माल, और मशीनरी जैसे उत्पादों पर भारत की निर्भरता चीन पर बनी हुई है। इससे न केवल आर्थिक घाटा उत्पन्न होता है, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से यह भारत को असुरक्षित बनाता है। हाल के वर्षों में भारत ने "मेक इन इंडिया", "आत्मनिर्भर भारत" और PLI स्कीम के तहत चीनी

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 15 Issue 06, June 2025,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में प्रयास किए हैं। इसके अलावा डिजिटल क्षेत्र में भी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, जैसे भारत द्वारा TikTok समेत कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाना और 5G नेटवर्क में HUAWEI की भूमिका पर रोक। रणनीतिक स्तर पर भारत और चीन वैश्विक मंचों पर प्रतिस्पर्धी हैं—चाहे वह इंडो-पैसिफिक रणनीति हो या BRICS में नेतृत्व की होड़। नेपाल, श्रीलंका और मालदीव जैसे पड़ोसी देशों में चीन के निवेश और राजनीतिक हस्तक्षेप ने भारत को अपने पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र में चुनौती दी है, जिससे दक्षिण एशिया में रणनीतिक अस्थिरता बढ़ी है। इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि भारत और अन्य पड़ोसी देशों पर चीन का प्रभाव बहुआयामी और चुनौतीपूर्ण है, जिसे केवल सैन्य या आर्थिक दृष्टि से नहीं, बल्कि समग्र भू-राजनीतिक रणनीति से समझने की आवश्यकता है।

चीन के बढ़ते प्रभाव से उत्पन्न अवसर

- **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी**

चीन के बढ़ते भू-राजनीतिक प्रभाव को अक्सर चुनौती के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसके समानांतर यह अनेक अवसर भी प्रस्तुत करता है, विशेषकर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के संदर्भ में। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) जैसी परियोजनाएँ, यदि पारदर्शिता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों पर आधारित हों, तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के देशों को आपस में जोड़ने वाली मजबूत परिवहन और व्यापारिक ढांचे की नींव रख सकती हैं। सड़क, रेल, बंदरगाह, और पाइपलाइन जैसे बुनियादी ढांचे के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा मिल सकता है। विशेषकर दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए यह कनेक्टिविटी क्षेत्रीय व्यापार को सुलभ बनाती है, जिससे लघु और मध्यम उद्योगों को नए बाजार मिल सकते हैं और रोजगार सृजन में मदद मिल सकती है। भारत यदि रणनीतिक समझदारी के साथ इस कनेक्टिविटी का लाभ उठाए, तो पूर्वोत्तर राज्यों की भौगोलिक बाधाओं को पार कर उन्हें वैश्विक व्यापार तंत्र से जोड़ा जा सकता है। साथ ही, यह पहल भारत को आसियान देशों, मध्य एशियाई गणराज्यों और अफ्रीका के साथ भी अधिक प्रभावशाली रूप से जोड़ सकती है।

- **निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के अवसर**

चीन की वैश्विक निवेश रणनीति, विशेष रूप से विकासशील देशों में, बुनियादी ढांचे के विकास के नए द्वार खोलती है। अफ्रीका, लातिन अमेरिका और दक्षिण एशिया में चीन द्वारा की गई भारी निवेश की

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 15 Issue 06, June 2025,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

परियोजनाएँ इस बात का प्रमाण हैं कि उसकी पूंजी और तकनीकी क्षमता का लाभ विकासशील देश उठा सकते हैं। भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देश यदि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए चीन के निवेश को नियंत्रित और विवेकपूर्ण ढंग से स्वीकार करें, तो वे सड़कों, रेलमार्गों, ऊर्जा संयंत्रों, स्मार्ट सिटी और औद्योगिक गलियारों जैसे क्षेत्रों में तीव्र विकास कर सकते हैं। चीन के पास निर्माण तकनीक, पूंजी, और परियोजना प्रबंधन का अनुभव है, जिससे तेज़ी से परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा सकता है। हालांकि इसमें सावधानी आवश्यक है ताकि संप्रभुता से समझौता न हो और ऋण-जाल जैसे खतरों से बचा जा सके। भारत की "नेबरहुड फर्स्ट" नीति के तहत, यदि पड़ोसी देशों के साथ मिलकर रणनीतिक रूप से चीन के संसाधनों का उपयोग हो, तो यह क्षेत्रीय समृद्धि को गति दे सकता है।

- **बहुपक्षीय मंचों पर साझेदारी की संभावनाएँ**

चीन के बढ़ते प्रभाव के चलते विश्व राजनीति में नए बहुपक्षीय मंच और गठबंधन बनते जा रहे हैं, जिनमें भारत के लिए भी सक्रिय भागीदारी के अवसर मौजूद हैं। ब्रिक्स (BRICS), शंघाई सहयोग संगठन (SCO), एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) जैसे मंचों में भारत और चीन दोनों की भागीदारी है, जिससे न केवल आर्थिक सहयोग बल्कि आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे साझा मुद्दों पर संयुक्त प्रयास किए जा सकते हैं। इन मंचों के माध्यम से भारत अपनी स्थिति को संतुलित रखते हुए वैश्विक शासन प्रणाली में अपनी भूमिका को मजबूत कर सकता है। साथ ही, यह बहुपक्षीय सहयोग भारत को चीन से प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सह-अस्तित्व और सहयोग के मॉडल की ओर प्रेरित कर सकता है। यह एक ऐसा परिदृश्य निर्मित कर सकता है जिसमें दोनों राष्ट्र अपने हितों की रक्षा करते हुए विकासशील देशों के लिए नेतृत्व प्रदान करें। इसलिए, भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के इस युग में चीन के बढ़ते प्रभाव को केवल खतरे के रूप में नहीं, बल्कि अवसर के रूप में भी देखने और अपनाने की आवश्यकता है—बशर्ते यह समझदारी, पारदर्शिता और रणनीतिक संतुलन के साथ किया जाए।

उभरती चुनौतियाँ: चीन के बढ़ते प्रभाव के गंभीर परिणाम

- **सुरक्षा और संप्रभुता पर खतरा**

चीन के बढ़ते भू-राजनीतिक प्रभाव से सबसे गंभीर चुनौती देशों की सुरक्षा और संप्रभुता पर पड़ने वाला खतरा है। चीन अपनी सैन्य शक्ति के विस्तार, आक्रामक विदेश नीति, और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की प्रवृत्ति के माध्यम से कई देशों की स्वतंत्रता को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 15 Issue 06, June 2025,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

विशेषकर भारत के संदर्भ में लद्दाख की गलवान घाटी में हुई सैन्य झड़प, अरुणाचल प्रदेश पर चीन के निरंतर दावे, और सीमा पर सैन्य गतिविधियों में वृद्धि यह दर्शाते हैं कि चीन की रणनीति पारंपरिक आक्रामकता की ओर झुकी हुई है। इसके अलावा, दक्षिण चीन सागर में चीन की विस्तारवादी नीति, कृत्रिम द्वीप निर्माण और अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में सैन्य चौकियों की स्थापना क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा संतुलन को अस्थिर कर रही है। यह न केवल समुद्री व्यापार के लिए खतरा है बल्कि संप्रभुता की अवधारणा को चुनौती भी देता है। छोटे देशों जैसे नेपाल, भूटान, और मालदीव की स्वतंत्र विदेश नीति पर भी चीन का आर्थिक और राजनीतिक दबाव धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जिससे उनकी रणनीतिक स्वतंत्रता सीमित हो रही है।

- **साइबर और सूचना युद्ध**

चीन आधुनिक युद्ध की नई परिभाषा—साइबर और सूचना युद्ध—के क्षेत्र में भी एक प्रमुख खिलाड़ी बन चुका है। चीन की सरकार समर्थित हैकिंग इकाइयाँ, जैसे APT (Advanced Persistent Threat) समूह, दुनिया भर की सरकारों, रक्षा प्रतिष्ठानों, और निजी कंपनियों को निशाना बना रही हैं। भारत सहित कई देशों ने चीनी साइबर हमलों के प्रयासों को पहचाना और रिकॉर्ड किया है, जिसमें बैंकिंग, दूरसंचार, और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में डेटा चोरी और सिस्टम हैकिंग शामिल है। इसके अतिरिक्त, चीन "सूचना नियंत्रण" और "प्रचार युद्ध" की रणनीति को भी लागू करता है, जिसके अंतर्गत वह सोशल मीडिया, न्यूज एजेंसियों, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से वैश्विक राय को प्रभावित करने का प्रयास करता है। यह न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए चुनौती है, बल्कि नागरिकों की सूचना तक पहुँच, विचारों की स्वतंत्रता और मीडिया की निष्पक्षता के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है। यदि इससे समय रहते सतर्कता नहीं बरती गई, तो यह आंतरिक स्थिरता को भी बाधित कर सकता है।

निष्कर्ष

भू-राजनीति में चीन का बढ़ता प्रभाव आज के वैश्विक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो अनेक अवसरों के साथ-साथ गंभीर चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है। चीन की तीव्र आर्थिक वृद्धि और वैश्विक परियोजनाएं, जैसे 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव', विकासशील देशों के लिए निवेश, व्यापार और बुनियादी ढांचे के विकास के नए अवसर पैदा कर रही हैं। इसके कारण कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं अधिक जुड़ी हुई हैं और वैश्विक आर्थिक समन्वय बढ़ रहा है। साथ ही, चीन की सैन्य शक्ति में वृद्धि और तकनीकी प्रगति ने उसे क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक महत्व के केंद्र में ला दिया है। लेकिन इस

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 15 Issue 06, June 2025,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

बढ़ते प्रभाव के कारण क्षेत्रीय विवाद, खासकर दक्षिण चीन सागर, तिब्बत और सीमाई क्षेत्रों में तनाव भी बढ़ा है। चीन की विदेश नीति और आर्थिक दबाव से कई विकासशील देशों की संप्रभुता पर प्रभाव पड़ रहा है, जिससे उनकी विदेश नीतियों और आंतरिक स्थिरता में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। चीन का बढ़ता प्रभाव वैश्विक शक्ति संतुलन को भी चुनौती दे रहा है, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ तनाव और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। ऐसे में, वैश्विक समुदाय के लिए यह आवश्यक है कि वे चीन के इस प्रभाव को समझदारी और सामरिक संतुलन के साथ संभालें। सतर्कता, कूटनीतिक संवाद और सहयोग के माध्यम से ही क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता बनाए रखना संभव होगा। इसलिए, चीन के बढ़ते प्रभाव को अवसरों के रूप में स्वीकार करते हुए उससे उत्पन्न चुनौतियों का सामूहिक समाधान ढूंढना आज की वैश्विक राजनीति की प्राथमिकता होनी चाहिए।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 15 Issue 06, June 2025,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

संदर्भ

1. टुडोरोईउ, टी. (2022). चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का भू-राजनीतिक महत्व. रूटलेज।
2. गांचेव, आई. (2021). बीआरआई के दस वर्ष: चीन का भू-राजनीतिक विस्तार और विकास. क्षेत्रीय एकीकरण संस्थान।
3. ईटन वांस. (2021). चीन की भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और चुनौतियां. ईटन वांस।
4. कार्नेगी एंडोवमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस. (2021). दक्षिण एशिया में चीन का प्रभाव: चार देशों की कमजोरियां और प्रतिरोध. कार्नेगी एंडोवमेंट।
5. मैकडेविट, एम. (2020). एशिया-प्रशांत में अमेरिका और चीन: नया क्षेत्रीय शीत युद्ध? टेलर एंड फ्रांसिस।
6. रिसर्चगेट. (2021). मध्य पूर्व में चीन का बढ़ता प्रभाव: अवसर, चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं. रिसर्चगेट।
7. वर्ल्ड सायंटिफिक. (2021). बीआरआई की उपलब्धियां और चुनौतियां. वर्ल्ड सायंटिफिक।
8. फाइनेंशियल टाइम्स. (2021). खनिजों पर भू-राजनीतिक संघर्ष: एक वास्तविक खतरा? फाइनेंशियल टाइम्स।
9. वॉल स्ट्रीट जर्नल. (2021). चीन द्वारा अमेरिका के साथ संघर्ष के लिए निर्मित किलेबंदी. वॉल स्ट्रीट जर्नल।
10. फाइनेंशियल टाइम्स. (2021). क्या स्टारलिंक ने नई अंतरिक्ष दौड़ पहले ही जीत ली है? फाइनेंशियल टाइम्स।
11. कार्नेगी एंडोवमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस. (2021). दक्षिण एशिया में चीन का प्रभाव: कमजोरियां और स्थिरता. कार्नेगी एंडोवमेंट।
12. हिंरिच फाउंडेशन. (2022). चीन में विदेशी कंपनियों के लिए बढ़ती चुनौतियां. हिंरिच फाउंडेशन।